राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग द्वारा विचार विमर्श सत्र
''टू स्टेट्स'' एक्सपीरियंस शेयरिंग एन इनीशियेटिव ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन''

जयपुर, 15 नवम्बर। राजस्थान वित्त आयोग की अध्यक्ष, डॉ. ज्योति किरण की अध्यक्षता में मंगलवार को होटल खासा कोठी में पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी निकायों की व्यवस्था, आर्थिक स्थिति एवं कार्यप्रणाली पर **''टू स्टेट्स'' एक्सपीरियंस शेयरिंग एन इनीशियेटिव ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन''** सत्र का आयोजन किया गया।

डॉ. ज्योति किरण ने राजस्थान वित्त आयोग द्वारा दिए गए दो अंतरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों एवं उनके महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालीन प्रभावों पर विचार विमर्श के दौरान प्रकाश डाला। उन्होंने कहा ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जनता के हित के लिए प्रशासन के नीचे के स्तर तक शोध किया है, जिससे जनता से सीधे जुड़ाव हो सके।

राजस्थान राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि आयोग ने सभी ग्राम पंचायतों से आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की हैं, राशियों के वितरण हेतु पिछड़ेपन के सूचकांक का उपयोग किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय व राज्य महत्व की योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु 40 प्रतिशत राशियों के प्रावधान किए हैं। भारत सरकार द्वारा पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का अनुदान बन्द करने के कारण पंचायत समितियों के अनुदान को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत एवं जिला परिषदों के अनुदान को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया है तथा राज्य सरकार द्वारा आयोग की रिपोर्ट को अक्षरशः स्वीकार कर लागू किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत कोठारी ने डॉ. ज्योति किरण द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश आयोग इनका अध्ययन कर उन्हें अपनाने के बारे में विचार करेगा। मध्यप्रदेश वित्त आयोग का गठन मई 2014 में हुआ था तथा यह आयोग अपने अन्तिम प्रतिवेदन की तैयारी कर रहा है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की भौगोलिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियाँ लगभग एक जैसी हैं। राजस्थान भ्रमण कार्यक्रम से यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों, व्यवस्थाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकलापों को नजदीकी से देखने का अवसर मिलेगा।

विचार विमर्श एवं अनुभव साझा करने के सत्र में राजस्थान राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव श्री एस.सी. देराश्री एवं नीति आयोग चेयर, प्रोफेसर श्री विजय वीर सिंह तथा अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग ने भी आयोग की गतिविधियों, अध्ययनों एवं किए जा रहे विशिष्ट कार्यों के बारे में विचार व्यक्त किए।

सत्र में मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के सदस्य सर्वश्री डी.आर.एस. चौधरी एवं श्री मलय कुमार रॉय तथा सदस्य सचिव, श्री सुशील कुमार द्विवेदी, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।